



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 820 राँची, शुक्रवार, 12 कार्तिक, 1938 (श०)  
3 नवम्बर, 2017 (ई०)

---

#### खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

-----  
संकल्प

11 जुलाई, 2017

**विषय:-** चीनी वितरण योजना हेतु अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुकों को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले प्रति किलोग्राम प्रतिमाह 18.50 रुपये के अनुदान के साथ चीनी वितरण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति।

संख्या-06-चीनी (नीतिगत मामले)-01/2017-खा.आ. - 2933-- W.P. PIL No. 2542/2010 श्री राम निवास प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 3101, दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 के द्वारा राज्य में चीनी वितरण योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था ।

02. विभागीय संकल्प संख्या 828, दिनांक 13 मार्च, 2015 के द्वारा राज्य में चीनी वितरण योजना के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया गया । इसके द्वारा मुख्यतः लाभुक दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् है:-

- लाभुक दर = चयनित निविदा से प्राप्त दर + अन्य व्यय - भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ।

03. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 253, दिनांक 27 जनवरी, 2016 के द्वारा राज्य में चीनी वितरण योजना एवं अन्य योजना हेतु सामान्य निविदा प्रणाली का परित्याग करते हुए NeML के ई-प्लेटफॉर्म की सेवा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया । विभागीय संकल्प संख्या 2717, दिनांक 15 जुलाई, 2016 द्वारा राज्य में चीनी वितरण योजना के तहत चीनी की पैकेजिंग में बदलाव का निर्णय लिया गया ।

04. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के D.O. No. 2(1)/2017-SP-I, दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुकों को चीनी पर 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान प्रदान किया जाता था । परन्तु अब सिर्फ अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित लाभुकों को ही प्रतिमाह 01 किलोग्राम चीनी पर 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान प्रदान किया जायेगा ।

05. वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य योजना मद से चीनी वितरण हेतु राशि आवंटित थी, साथ ही साथ इस अवधि में वितरण के विरुद्ध केन्द्रीय अनुदान भी प्राप्त हुआ था । इस प्रकार केन्द्रीय अनुदान एवं लाभुकों से प्राप्त राशि को रिवॉल्विंग फण्ड में संधारित की जाती है । इस प्रकार एक परिक्रामी निधि का निर्माण हो चुका है जिसमें अभी लगभग 364 (तीन सौ चैंसठ) करोड़ रुपये की राशि एकत्रित है ।

06. वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु राज्य के बजट में चीनी वितरण योजना के लिए 150 (एक सौ पचास) करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

07. चीनी वितरण योजना का कराये गये थर्ड पार्टी मूल्यांकन में यह बात उभरकर आयी है कि इस योजना को राज्य की 99.60 प्रतिशत जनता चालू रखने के पक्ष में है । इस प्रकार यह सरकार की एक जन-लोकप्रिय योजना साबित हुयी है ।

08. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 से चीनी वितरण योजना के मद में राज्य के अन्त्योदय अन्न योजना के सभी लाभुकों को केन्द्रीय अनुदान (18.50 रुपये प्रति किलोग्राम) के साथ प्रतिमाह प्रति परिवार 01(एक)किलोग्राम चीनी प्रदान किया जायेगा । इस मद में पूर्व में प्राप्त केन्द्रीय अनुदान तथा लाभुकों से प्राप्त राशि का उपयोग/व्यय परिक्रामी निधि के रूप में किया जायेगा ।

09. अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुकों को चीनी प्रदान करने पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रति किलोग्राम 18.50 रुपये का अनुदान वहन करने पर लाभुक दर पूर्व की भांति ही निम्नवत् निर्धारित किया जायेगा:-

- प्रति किलोग्राम लाभुक दर = चयनित आपूर्तिकर्ता से प्राप्त दर + अन्य प्रशासनिक व्यय - केन्द्र सरकार के द्वारा प्रति किलोग्राम वहन किया गया अनुदान रुपये 18.50 प्रति किलोग्राम ।

10. अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुकों को चीनी प्रदान करने पर केन्द्र सरकार द्वारा रुपये 18.50 प्रति किलोग्राम प्रतिमाह अनुदान प्रदान किया जाना है । अतः उपरोक्त लाभुक दर निर्धारण प्रणाली के आधार पर चीनी वितरित करने पर राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा । आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान हेतु परिक्रामी निधि में संचित राशि का सहयोग लिया जायेगा जिसका सामंजन केन्द्र सरकार/लाभुकों से प्राप्त राशि से किया जायेगा । वर्तमान में राज्य में कुल 9,08,353 अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवार हैं ।

11. विभागीय संकल्प संख्या 2717, दिनांक 15 जुलाई, 2016, संकल्प संख्या 828, दिनांक 13 मार्च, 2015 एवं संकल्प संख्या 3101, दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

12. इस संकल्प से संबंधित विभागीय संलेख संख्या 2797 दिनांक 28 जून, 2017 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 4 जुलाई, 2017 की बैठक में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनय कुमार चौबे,**  
सरकार के सचिव ।

-----